



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की, वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

‘सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी

जयपुर, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घंटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रक्टर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उससे वसूली की जाएगी। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त

- मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे कराकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।**

कार्यवाही होगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून

के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करवाया जाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के

लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय

चर्चा है कि जेडीयू 102, भाजपा 101, चिराग पासवान 20, मांझी व उपेन्द्र कुशवाह 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

- कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तो लगभग तय हो गया है, पर कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, इस पर चिंतन जारी है।**

गठबंधन की सीट शेर्यरिंग की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन आगे होगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। सीधे बीच अब सीटों का ये आंखड़ा आया है। जेडीयू को अधिक सीटें देकर यह बतावे की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
2000 से अधिक लोगों का अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है। शिविरों में रहने, खाने और सोने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।

अमेरिकी वीजा की अवधि घटाई जाएगी?

वाशिंगटन, 28 अगस्त। अमेरिकी प्रशासन अपने वीजा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और अगर ये नियम स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे वीजा धारकों की समयवधि घट जाएगी। इससे वहां रह रहे लोगों खासकर छात्रों को अपने देश जल्द वापस लौटना पड़ सकता है।

अमेरिकी गृह विभाग ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित नियम अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इससे वीजा के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और शासन की इन व्यक्तियों की जांच और निगरानी करने को क्षमता बढ़ेगी। यह नियम कुछ ही तरह की वीजा श्रेणी पर लागू होगा और इस श्रेणी में विदेशी छात्रों

- अगर ऐसा हुआ तो वहां काम या पढ़ाई के लिए गए लोगों को जल्दी ही लौटना पड़ सकता है।**

को मिलने वाला वीजा भी शामिल है। अमेरिका के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है।” विदित हो कि सन 1978 से, यहां आने वाले विदेशी छात्रों को एच श्रेणी का वीजा एक खास अवधि के लिए दिया जाता रहा है। अन्य वीजा श्रेणी से भिन्न यह वीजा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। अब अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि विदेशी छात्रों ने अमेरिकी उदारता का लाभ उठाया है और वे ऐसे “स्थायी” छात्र बन गए हैं, जो अमेरिका में रहने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थायी रूप से खुद का नामांकन किए रहते हैं।

बिहार में घुसे तीन संदिग्धों पर 5 0 हजार का इनाम घोषित

तीनों पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल की सीमा से बिहार में घुसे हैं राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है

- इस घटनाक्रम के बाद राहुल की वोट अधिकार यात्रा में भी बदलाव किया गया है अब वे खुली जीप की बजाय बंदगाड़ी से यात्रा कर रहें हैं।**

शामिल हैं। पुलिस की ओर से इन तीनों संदिग्धों के नाम, तस्वीर सार्वजनिक कर दिये गये हैं।

पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है।

वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया

मोदी जापान और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
देशों के प्रमुख से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर मैं 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम इस यात्रा के दौरान अपनी वैश्विक रणनीतिक और वैश्विक सझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर

होगी जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं।(पीएम ने कहा कि जापान से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर कियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाऊंगा। भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। सात साल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नजदीकी बंधा ाकर मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्थन जुटाएंगे।

‘वैश्विक नेताओं से निजी ...

- इसके लिए भारत पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कभी टैरिफ बढ़ाकर कभी एच वन-बी वीजा के नाम पर तो कभी ऑपरेशन सिंदूर व सीज़फायर पर दावे करके तो कभी रुस -यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताकर।**
- प्र.मंत्री मोदी ने भी इस दबाव को स्वीकार किया और कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, हम उसे सहन करेंगे पर हम किसानों, पशुपालकों व लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।**

चाहता है कि भारत कृषि बाज़ार को उसके उत्पादों के लिए खोले जो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा भारतीय किसानों की बर्बादी।

एक वरिष्ठ राजनयिक ने जब पूछा गया कि अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ा है, तो उन्होंने कहा: ये सब अर्थव्यवस्था के कारण है।”

वाइट हाउस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि “यह केवल रूसी तेल के बारे में नहीं है।”

बेसेंट ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौता वार्ताओं में केवल “दिखावा” किया है।

नवरो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान नेता” बताया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वह इस सिद्धांत

को मजबूत करता है कि वाशिंगटन की असली चिंता भारत की व्यापारिक बाधाएँ हैं।

नवरो ने कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि “भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहाँ बुद्धिमान लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन वे हमसे आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि ‘हमारे टैरिफ दुनिया में सबसे ऊँचे नहीं हैं’, जबकि सच्चाई यह है कि वे सबसे ऊँचे हैं।”

भारत पर अमेरिकी दबाव का एक और पहलू है – ट्रम्प प्रशासन की एच वन-बी वीजा कार्यक्रम को लेकर नाराजगी, जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड

लुटनिक ने बुधवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन एच वन-बी कार्यक्रम में बदलाव की योजना बना रहा है, जो

भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच सबसे लोकप्रिय गैर-प्रवासी वीजा है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

लुटनिक ने कहा: “मैं एच वन-बी कार्यक्रम को बदलने में शामिल हूँ। हम इस कार्यक्रम को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत खराब है।”

ऑपरेशन सिंदूर भी दबाव का बिन्दू है। ट्रम्प ने मंगलवार को फिर भारत के इस दावे का खंडन किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि इस झड़प में भारत ने अपने सबसे महंगे राफेल जेट खो दिए।

ट्रम्प के ये बार-बार के दावे सीधे-सीधे उनके मित्र नेरेंद्र मोदी की सरकार को उस स्थिति पर हमला हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी विदेशी सरकार ने सैन्य अभियान रोकने का दबाव नहीं डाला। प्रधानमंत्री ने स्वयं बड़ावा को स्वीकार किया। सोमवार को, जब अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ पूरी तरह लागू होने में दो दिन बाकी थे, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार “किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों पर समझौता नहीं कर सकती।”

उन्होंने यह भी कहा: हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम उसे सहन करेंगे।

भारत ने ट्रंप की ‘‘टैरिफ ...

- पर, यह भी सच है कि, दीर्घकाल की दृष्टि से, भारत की यह सामना करने की नीति लाभकारी ही रहेगी, पर तत्कालिक रूप से आर्थिक पीड़ा जरूर होगी, क्योंकि भारत के अमेरिका को निर्यात होने वाले 45अरब डॉलर के माल पर भारी संकट आयेगा, कुछ रोजगार भी खत्म हो जायेंगे ।**

गति पर विवाद है, लेकिन यह सुधार अनुपालन को सरल बनाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है। यह भारत के सुधार एजेंडे की निरंतरता को भी दर्शाता है, जिससे निवेशकों को यह परीक्षा मिलता है कि बाहरी उथल-पुथल से आंतरिक नीतिगत प्रगति बाधित नहीं होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गोबा के नेतृत्व में दो उच्चस्तरीय समितियाँ नियामक छूट और संरचनात्मक सुधारों के खके तैयार कर रही हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री

सलाह देती है यानि प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद। यह दिखाता है कि भारत बाहरी झटकों के जवाब में दीर्घकालिक योजना और त्वरित आर्थिक सलाह दोनों को सक्रिय रूप से जुटा रहा है।

अल्पकाल में, टैरिफ वृद्धि से नुकसान होगा। श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को दबाव का सामना करना पड़ेगा, और वैकल्पिक बाजार विकसित होने से पहले व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। फिर भी, मोदी सरकार इस अस्थिरता को एक उल्टेपक्ष के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। घरेलू खपत पर दंव लगाकर, सुधारों में तेजी लाकर और वैश्विक सझेदारियों में विविधता लाकर, नई दिल्ली टैरिफ झटके को दीर्घकालिक लाभ में बदलने की रणनीति अपना रही है। हालाँकि इसका लाभ असमान रूप से मिलेगा। अल्पकालिक दर्द टालना संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका लाभ एक अधिक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकती है – जो वाशिंगटन को व्यापार नीति की अनिश्चितताओं से कम प्रभावित हो, और अपनी घरेलू मांग व विविध वैश्विक संबंधों पर अधिक आधारित हो।